केंद्रीय बैंकों की खरीद से सोना महंगा

वैश्विक मांग से बढ़ीं कीमतें, आरबीआई रखे हुए है नजर : वित्त मंत्री सीतारमण

नयी दिल्ली, 23 फरवरी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सोने की कीमतों में इस समय चल रही तेजी मुख्य रूप से दुनिया के केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने-चांदी की खरीद बढ़ाये जाने के कारण है.

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि देश में सोने के निवेश और उपभोग मांग को देख कर ऐसा नहीं लगता कि स्थिति चिंता के स्तर पर है फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की बाजार पर निगाह बनी हुई है. श्रीमती सीतारमण आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की बजट पश्चात बैठक में भाग लेने के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रही थी. वित्त मंत्री ने कहा, 'आजकल अधिकांश देश, विशेष रूप से उनके केंद्रीय बैंक, सोना और चांदी खरीदकर भंडारित कर रहे हैं. जब आप भारतीय उपभोक्ता बाजार की बात करते हैं, तो यह एक प्रवृत्ति के रूप में दिखता है. हर केंद्रीय बैंक के पास कुछ न कुछ भंडार होता है, लेकिन हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कई अन्य देशों के केंद्रीय बैंक भी सोना खरीद रहे हैं.' उन्होंने कहा,' कीमतों में जो उछाल आया है, वह मुख्य रूप से केंद्रीय बैंकों द्वारा सोना खरीदने और उसे संग्रहित करने के कारण है.'

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में सोना हमेशा से परिवारों के लिए एक पसंदीदा निवेश रहा है. घरेलू उपभोग की उच्च मांग में त्योहारों के मौसम के दौरान मौसमी उछाल भी देखने को मिलता है. उन्होंने कहा,' हम इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह किसी चिंताजनक स्तर तक पहुंचा है. मेरा मानना है कि यह एक निश्चित सीमा से आगे नहीं गया है. हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक भी इस पर निगरानी रखे हुए है.' रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस वर्ष अप्रैल-दिसंबर 2025 तक के स्वर्ण आयात के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें एक साल पहले की तुलना में मूल्य के हिसाब से कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता.

श्रीमती सीतारमण ने घरेलू उपभोग के बारे में कहा कि यह हर मौसम और हर त्योहार के साथ जुड़ी एक सामान्य स्थिति रहती है. लेकिन सोनेऔर चांदी की वैश्विक कीमतों में जो असामान्य और सामान्य उतार-चढ़ाव से कहीं अधिक वृद्धि हुई है, उसका प्रभाव हर घरेलू खरीद पर पड़ रहा है. उन्होंने कहा,' कीमती धातुओं के मामले में हमारी निर्भरता लगभग पूरी तरह बाहरी स्रोतों पर है. हमारे पास सोने की खोज और उसके खनन का पर्याप्त घरेलू स्रोत नहीं है.

एआई से रियल-टाइम निगरानी की तैयारी

नई दिल्ली, 23 फरवरी. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (पीएमएस), लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (एलओडीआर) और सेटलमेंट ढांचे की समीक्षा की घोषणा की है. सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने बताया कि निवेशक हित को केंद्र में रखते हुए मौजूदा नियमों और फ्रेमवर्क में सुधार की जरूरत है. इस समीक्षा के लिए जून में कंसल्टेशन पेपर जारी किया जा सकता है, जिसमें विशेषज्ञों और बाजार सहभागियों से राय ली जाएगी.

पांडेय ने यह भी बताया कि सेबी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के माध्यम से रियल-टाइम निगरानी की संभावनाओं पर काम कर रहा है. इसका उद्देश्य बाजार की गड़बड़ियों को तुरंत पहचानना और समाधान करना है.

शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन तेजी

479 अंक की बढ़त से रहा सेंसेक्स

141 अंक से आगे रहा निफ्टी

मुंबई, 23 फरवरी अमेरिका में आयात शुल्क में कमी से सोमवार को घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन तेजी रही.

बीएसई का सेंसेक्स 479.95 अंक (0.58 अंक) की बढ़त में 83,294.66 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 141.75 अंक यानी 0.55 प्रतिशत ऊपर 25,713 अंक पर बंद हुआ.

सार्वजनिक बैंकों, वित्तीय कंपनियों और एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियों में ज्यादा लिवाली रही. आईटी, रसायन, धातु, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद और रियलटी समूहों के सूचकांक टूट गये. मझौली कंपनियों में बिकावाली और छोटी कंपनियों में लिवाली ज्यादा रही. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.83 प्रतिशत फिसल गया जबकि स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.29 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ.

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले साल विभिन्न देशों पर लगाये गये आयात शुल्क की ऊंची दरों को अवैध बताते हुए उसे रद्द कर दिया था. इसके बाद श्री ट्रंप ने 20 फरवरी को 150 दिन के लिए सभी देशों पर 10 प्रतिशत का समान आयात शुल्क लगाने की घोषणा की थी जिसके बारे में व्हाइट हाउस ने आदेश भी जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि नयी दर 24 फरवरी से लागू होनी है. हालांकि राष्ट्रपति ने 21 फरवरी को आयात शुल्क 15 प्रतिशत करने की घोषणा की थी, लेकिन इसके बारे में अबतक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है.

एमबीडी और रेडिसन समूह मिलकर खोलेंगे 50 नये होटल

अगले 10 साल में 80% प्रबंधित और फ्रेंचाइज़ी होटल

नोएडा का होटल रेडिसन कलेक्शन में बदलेगा

नोएडा, 23 फरवरी एमबीडी समूह और रेडिसन समूह ने अपनी साझेदारी को और आगे बढ़ाते हुए सोमवार को नये ब्रांड बनाने के साथ देश में अगले 10 साल में 50 नये होटल खोलने की घोषणा की.

एमबीडी समूह की संयुक्त प्रबंध निदेशक सोनिका मल्होत्रा कंधारी ने बताया कि नये ब्रांड रेडिसन कलेक्शन एमबीडी और रेडिसन रेड एमबीडी के नाम से जाने जाएंगे. रेडिसन कलेक्शन एमबीडी लग्जरी होटल होंगे जबकि रेडिसन रेड एमबीडी लाइफस्टाइल श्रेणी के होटल होंगे. उन्होंने बताया कि अधिकांश होटल एसेट-लाइट मॉडल के माध्यम से विकसित होंगे. एमबीडी की संपत्ति हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत रहेगी. लाइफस्टाइल सेगमेंट में अधिक आक्रामक विस्तार का लक्ष्य है. प्रस्तावित पोर्टफोलियो में लगभग 80 प्रतिशत प्रबंधित और फ्रेंचाइजी होटल तथा 20 प्रतिशत स्वामित्व वाले होटल शामिल होंगे. बेंगलुरु, उदयपुर और रणथंभौर में जमीन खरीदने का काम हो चुका है.

इस रणनीतिक साझेदारी के तहत एमबीडी समूह देश भर में रेडिसन कलेक्शन और रेडिसन रेड होटलों के विकास में मदद करेगा. एमबीडी ग्रुप चिह्नित और आपसी सहमति वाले स्थानों पर दोनों ब्रांड के लिए कारोबार विकास, प्रबंधन और फ्रेंचाइज़िंग की जिम्मेदारी भी निभायेगा.

रेडिसन होटल ग्रुप के दक्षिण एशिया कारोबार के प्रबंध निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी निखिल शर्मा ने कहा, 'भारत के प्रीमियम आतिथ्य बाजार में लगातार मजबूत वृद्धि देखी जा रही है. समकालीन, डिजाइन-आधारित लाइफस्टाइल अनुभवों की मांग बढ़ रही है. यह रणनीतिक साझेदारी हमें प्रमुख भारतीय बाजारों में रेडिसन कलेक्शन और रेडिसन रेड के विस्तार को और सशक्त करने में मदद करेगी.

रेलवे निवेश से अवसंरचना विकास को ऐतिहासिक गति

87 स्टेशनों का पुनर्विकास, यात्री सुविधाओं और सौंदर्य में सुधार

अहमदाबाद, 23 फरवरी .भारतीय रेलवे ने गुजरात में रिकॉर्ड निवेश के साथ रेल अवसंरचना के विकास को नई ऊंचाई दी है. वर्ष 2026-27 के लिए राज्य को ?17,366 करोड़ का ऐतिहासिक बजटीय आवंटन मिला है, जिससे कनेक्टिविटी, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं के विस्तार को अभूतपूर्व गति मिली है. तुलना करें तो 2009-14 के दौरान गुजरात के लिए औसत वार्षिक आवंटन मात्र ?589 करोड़ था—यानी अब लगभग 29 गुना वृद्धि.

वर्तमान में गुजरात में ?1,28,748 करोड़ की रेलवे परियोजनाएं प्रगति पर हैं. इनमें नई रेल लाइनों का निर्माण, स्टेशनों का पुनर्विकास और प्रमुख सुरक्षा उन्नयन शामिल हैं. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली से गुजरात तक औद्योगिक व बंदरगाह क्षेत्रों को जोड़ता है, जबकि सूरत में महत्वपूर्ण जंक्शन विकसित किया जा रहा है, जिससे पूर्व-पश्चिम लॉजिस्टिक्स को मजबूती मिलेगी. गुजरात ने 100% रेल विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है. राज्य में 87 स्टेशनों पर निर्माण कार्य जारी है. अहमदाबाद-मुंबई हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) परियोजना तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इसके व्यावसायिक संचालन का लक्ष्य अगले वर्ष रखा गया है.

अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत 6,058 करोड़ की लागत से 87 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें 19 स्टेशन पूर्ण हो चुके हैं. आधुनिक ट्रेन सेवाओं से यात्री अनुभव बेहतर हुआ है—राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस (6), अमृत भारत एक्सप्रेस (1) और नमो भारत एक्सप्रेस (1) संचालित हैं. 2014 के बाद लगभग 2,900 किमी नई रेल लाइनें बिछी हैं, 4,005 किमी मार्ग विद्युतीकृत हुए हैं और 1,177 फ्लाईओवर/अंडरपास बने हैं. उन्नत सुरक्षा प्रणालियों के साथ यह निवेश गुजरात की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को मजबूत आधार दे रहा है.

बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन्स में आई गिरावट

मुंबई, 23 फरवरी. सोमवार को जब स्टॉक मार्केट में तेजी थी, उसी समय क्रिप्टोकरेंसी का बाजार धड़ाम हो गया. पिछले 24 घंटे में वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप करीब 4% गिरकर 2.25 ट्रिलियन डॉलर रह गया. यानी निवेशकों को सिर्फ एक दिन में लगभग 0.08 ट्रिलियन डॉलर यानी 7.26 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

इस गिरावट से बिटकॉइन और पाई नेटवर्क जैसी प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी भी अछूती नहीं रहीं.इसके अलावा ईटीएफ से लगातार हो रहे आउटफ्लो ने भी बिकवाली के दबाव को बढ़ाया. ऑन-चेन डेटा के अनुसार, व्हेल्स 'डूब-शेप' में जमाखोरी कर रहे हैं, जिससे दबाव कुछ हद तक कम हुआ.

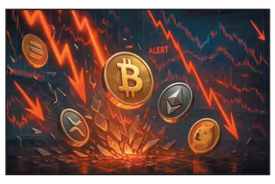

दोपहर 12:30 बजे बिटकॉइन 3% की गिरावट के साथ 65,790 डॉलर, इथेरियम लगभग 5% गिरकर 1,880 डॉलर और रिपल 4% की गिरावट के साथ 1.36 डॉलर पर कारोबार कर रहा था. पाई नेटवर्क भी 5% से अधिक की गिरावट के साथ 0.1580 डॉलर पर था. विशेषज्ञों का मानना है कि इस गिरावट का मुख्य कारण डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया के अधिकांश देशों पर 15% फ्लैट टैरिफ लगाने की घोषणा है.

ब्रोकरों के लिए बैंक गारंटी नियमों में बदलाव नहीं : आरबीआई

नई दिल्ली, 23 फरवरी. आरबीआई के नए ब्रोकर फंडिंग नियम वित्तीय बाजार में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम हैं. नए नियमों के तहत बैंकों को ब्रोकरों और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स को दिए जाने वाले कर्ज में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं.

सबसे प्रमुख बदलाव कोलेटरल की शर्तों में सख्ती है, जिससे ब्रोकरों को बैंक गारंटी लेने में अधिक प्रमाण और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी. इसके अलावा, बैंकों को अब प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए कर्ज देने की अनुमति नहीं होगी. आरबीआई ने महंगाई लक्ष्य पर भी सरकार को अपनी सिफारिशें भेजी हैं. भारत में खुदरा महंगाई दर को 4% पर बनाए रखने का लक्ष्य है, जिसमें 2% से 6% का दायरा निर्धारित है. हाल ही में खुदरा महंगाई की गणना में बदलाव करते हुए खाद्य पदार्थों के हिस्से को कम किया गया है, जिससे महंगाई आंकड़ों में अधिक सटीकता आएगी. गवर्नर ने कहा कि इन बदलावों का मौजूदा महंगाई लक्ष्य पर कोई असर नहीं होगा.

स्मार्टफोन ने ऑटो डीजल को पछाड़ा

नई दिल्ली. 2025 में भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला उत्पाद अब एप्पल का आईफोन बन गया है. इंडस्ट्री डेटा के अनुसार इस दौरान लगभग 23 अरब डॉलर का आईफोन मुख्य रूप से अमेरिका को निर्यात किया गया. यह उछाल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और चीनी आपूर्तिकर्ताओं से विविधीकरण की वजह से आया. जनवरी-दिसंबर 2025 में स्मार्टफोन निर्यात 30.13 अरब डॉलर तक पहुंच गया, यह ऑटोमोबाइल डीजल ईंधन जैसी लंबी समय से शीर्ष निर्यात श्रेणी को पीछे छोड़ गया.

भारत अभी नंबर 1 नहीं बनेगा तो कब बनेगा?

नयी दिल्ली, 23 फरवरी वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि परोपकारी सोच वाली उद्यमिता के साथ सरकार का प्रोत्साहन देश को दुनिया में नंबर-1 बना सकता है, और इसके लिए यह बिल्कुल सही समय है.

श्री अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में यह बात कही. उन्होंने हिस्ट्री चैनल की एक श्रृंखला का जिक्र करते हुए अपनी बात शुरू की जिसमें अमेरिका के निर्माण के कर्णधारों के रूप में सिर्फ उद्यमियों को चुना गया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'अमेरिका को किसने बनाया? आपको जानकर आश्चर्य होगा - न कोई राजनेता, न वैज्ञानिक और न ही कोई बुद्धिजीवी. इस विषय पर हिस्ट्री चैनल की एक शानदार श्रृंखला है, जिसमें उन्होंने केवल उद्यमियों को चुना है.'

हिस्ट्री चैनल ने कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट, एंड्रयू कार्नेगी, जॉन रॉकफेलर, जे.पी. मॉर्गन और हेनरी फोर्ड को चुना है जिन्होंने क्रमशः अवसंरचना, इस्पात, तेल, बैंकिंग और ऑटोमोबाइल जैसे बुनियादी और प्रमुख उद्योगों की नींव रखी.

श्री अग्रवाल ने लिखा, 'इस भारत का निर्माण कौन करेगा? हमें अपने उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिये, उन पर विश्वास करना चाहिये, उन्हें सम्मान और गरिमा देनी चाहिये. वे परिसंपत्तियां बनाएंगे, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करेंगे, रोजगार सृजन करेंगे, राजस्व में योगदान देंगे और देश के उत्थान को गति देंगे.'

समाचार विशेष

ओवैसी ने उड़ाई तेजस्वी की नींद!

राज्यसभा के लिए अपना कैंडिडेट उतारेगी

पटना. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह इस बार राज्यसभा के लिए अपना कैंडिडेट उतारेगी और किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं बनी है.

पार्टी विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि हम सिर्फ सपोर्ट देने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आई है. उन्होंने सवाल किया, क्या मैं सिर्फ सपोर्ट देने के लिए पैदा हुआ हूं? पहले यह पूछो कि मुझे कौन सपोर्ट करेगा.ज उन्होंने कहा कि अभी उनकी पार्टी का राज्यसभा में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए एआईएमआईएम चाहती है कि हाउस में उसकी आवाज सुनी जाए.

अख्तरुल ईमान ने केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में जो लोग कम्युनल ताकतों से लड़ना चाहते हैं और दलितों, पिछड़े वर्गों और दबे-कुचले वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें एआईएमआईएम का सपोर्ट करना चाहिए. उन्होंने कहा कि पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी हमेशा समाज के कमजोर वर्गों की आवाज उठाते हैं. जब भी देश में कहीं भी कम्युनल टेंशन होता है, तो वह सबसे पहले अपना सपोर्ट दिखाते हैं.

ओवैसी के शागिर्द ने की बड़ी अपील- ईमान ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से ओवैसी की स्थिति मजबूत करने और एआईएमआईएम की राज्यसभा में एंट्री पक्की करने की अपील की, ताकि पार्टी संसद के ऊपरी सदन में अपनी बात मजबूती से रख सके. पार्टी का मानना है कि अब समय आ गया है कि वह सिर्फ समर्थन से आगे बढ़कर लीडरशिप की भूमिका निभाए.

दिलचस्प हुआ राज्यसभा चुनाव

बिहार से पांच राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है. जिसमें से दो-दो सीटों पर भाजपा और जदयू के उम्मीदवारों का उच्च सदन पहुंचना तय माना जा रहा है. लेकिन पांचवीं सीट के लिए एनडीए को तीन वोटों की जरूरत होगी. जबकि विपक्षी गठबंधन को अपना उम्मीदवार जिताने के लिए 6 विधायकों के वोट जरूरी होंगे. ऐसे में अगर विपक्षी गठबंधन को एआईएमआईएम के पांच और बसपा के एक विधायक का साथ मिल जाए तो उनका उम्मीदवार उच्च सदन में पहुंच सकता है. लेकिन अख्तरुल ईमान के इस ऐलान ने चुनाव को एनडीए की तरफ मोड़ते हुए दिलचस्प बना दिया है.

बीजद दूसरी सीट जीतना चाहेगी

भुवनेश्वर. ओडिशा में राज्यसभा की चार सीटों के लिए चुनाव होंगे. वैसे तो चारों सीटें पिछले दो वार्षिक चुनाव में बीजू जनता दल ने जीते थे. लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजद के हार कर सत्ता से बाहर होने के बाद दो सांसदों ने पाला बदल लिया. वे भाजपा के साथ चले गए.

सुजीत कुमार और ममता मोहंता भाजपा में चले गए हैं. इस तरह दो सीटें भाजपा की हैं और दो बीजू जनता दल की. ओडिशा की 147 सदस्यों की विधानसभा में भाजपा के पास 82 विधायक हैं. राज्य में एक सीट जीतने के लिए 29 वोट की जरुरत है. इस लिहाज से भाजपा आराम से दो सीटें जीत लेगी. लेकिन उसके बाद भाजपा के पास ज्यादा से ज्यादा 22 वोट बचेंगे. दूसरी ओर बीजू जनता दल के 48 विधायक हैं, जिनके दम पर वह एक सीट जीत लेगी और उसके पास 19 वोट बचेंगे. दूसरी सीट जीतने के लिए उसे 10 अतिरिक्त वोट की जरुरत होगी. कांग्रेस के पास राज्य विधानसभा में 14 विधायक हैं. अगर कांग्रेस और बीजू जनता दल मिल जाएं तो चौथी सीट जीत सकते हैं. कांग्रेस की ओर से बीजद को प्रस्ताव दिया गया है कि दोनों पार्टियां मिल कर किसी निर्दलीय को उम्मीदवार बना दें.

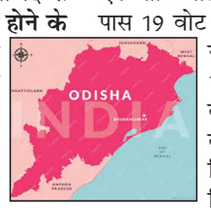

रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री?

पटना. बिहार में राज्यसभा की पांच सीटें खाली होने वाली हैं. 16 मार्च (2026) को मतदान होना है. अधिसूचना जारी होने के साथ ही बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है. सवाल है कि क्या मौजूदा सांसद रिपीट होंगे? अगर नहीं होंगे तो किसे मौका मिलेगा? ऐसी बातों की चर्चा शुरू हो गई है.

पांच सीटों पर मजबूत दावा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का है. बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही यह तय माना जा रहा था कि खाली हो रही राज्यसभा सीटों में से दो पर जेडीयू तो दो सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजेगी. वहीं एक अन्य सीट पर यह दोनों पार्टियां अपने सहयोगी दलों को एडजस्ट करेंगी, लेकिन इस एक सीट पर दावेदार तीन दल हैं.

चिराग पासवान की पार्टी दावेदारी में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और तीसरे पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है. हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी को हल्के में नहीं ले सकते हैं. उनकी दावेदारी इसलिए भी मजबूत होती है क्योंकि वह बीजेपी कोटे से ही राज्यसभा गए हैं.

2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को कम सीट मिली थी तो चर्चा तेज हुई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को एक राज्यसभा और एक बिहार विधान परिषद की सीट मिल सकती है. बात चिराग पासवान की करें तो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी 35 सीटों पर दावा ठोक रही थी. एनडीए में जब सीटों का फॉर्मूला सामने आया उसके बाद चिराग पासवान की नाराजगी दिखने लगी थी. डैमेज कंट्रोल के लिए दिल्ली से दो प्रमुख नेताओं को चिराग पासवान को समझाने और मैनेज करने के लिए भेजा गया था.

चिराग को मिला ऑफर तो किसे भेजेंगे राज्यसभा?

ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी से किसे भेजेंगे? क्योंकि एनडीए में चिराग पासवान को कोई दल नाराज नहीं कर सकता है. ऐसे में एक सीट जो है वह एलजेपीआर को दी जा सकती है. यानी चिराग पासवान किसी को राज्यसभा भेज सकते हैं. चर्चा यह भी है कि अगर राज्यसभा की एक सीट एलजेपी रामविलास के पाले में आती है तो इस सीट से वे अपनी मां रीना पासवान को राजसभा भेज सकते हैं.

विशेष | **क्या भाजपा- सपा को घेरने की है तैयारी?**

मायावती के अकेले चुनाव लड़ने का क्या है मतलब?

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं. समाजवादी पार्टी एक बार फिर विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरती दिख सकती है.

वहीं, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल एस, निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एकजुट रहना तय माना जा रहा है. भले ही चुनाव के समय तक कुछ उठापटक होती दिखे, लेकिन आखिर में एनडीए बिहार चुनाव 2025 की तरह एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरती दिख सकती है. वहीं, मायावती ने अपने पत्ते साफ कर दिए हैं. उन्होंने अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है. लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से मायावती लगातार पार्टी को एक बार फिर जमीन पर मजबूत बनाने की रणनीति पर काम करती दिख रही हैं. ऐसे में विधानसभा चुनाव 2027 पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है.

क्या है मायावती की घोषणा?- मायावती ने यूपी चुनाव 2027 को लेकर साफ कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी इसमें अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी. मायावती ने साफ कहा है कि इन दिनों अर्टिफिशियल इंटलीजेंस (एआई) को सफलता की कुंजी बताने की स्वार्थी चर्चाएं चल रही है. इन सबके बीच मीडिया जगत में भी किसी न किसी बहाने बसपा के गठनबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ने का भ्रम फैलाया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फेक न्यूज है. मायावती ने कहा कि कई बार सार्वजनिक तौर पर बसपा के अकेले चुनाव लड़ने की बात कही जा चुकी है. बसपा प्रमुख ने कहा कि 9 अक्टूबर 2025 को बसपा के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ में आयोजित महारैली में भी इसकी खुली घोषणा हुई थी. इसलिए, अब ऐसी किसी भी चर्चा और बहस की कोई संभावना नहीं बची है. इसके बाद भी भ्रामक खबरों को फैलाया जा रहा है.

जमीन पर उतरने की रणनीति

बसपा प्रमुख मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कैडरों को सक्रिय कर दिया है. बसपा हमेशा कैडर आधारित पार्टी रही है. पार्टी ने जमीनी स्तर से नेतृत्व तैयार प्रदेश में सफलता हासिल की है. बसपा में सफल होने के बाद नेता दूसरों दलों की राह पकड़ते दिखे हैं. ऐसे में पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं के सहारे एक बार फिर खोए जनाधार को पाने की कोशिश में है. इसमें गठबंधन की राजनीति से पार्टी को कोई बड़ा लाभ होता नहीं दिखा. 2019 में सपा के साथ गठबंधन के बाद बसपा के दलित वोटों में बिखराव दिखा. विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान बसपा से छिटके दलित वोटरों ने भाजपा का साथ दिया तो पार्टी ने ऐतिहासिक सफलता दर्ज की. कोई पार्टी लगभग साढ़े तीन दशक बाद लगातार दूसरी बार सत्ता में आने में कामयाब हुई. हालांकि, संविधान को खत्म करने की बात को जनता में स्थापित कर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में खेल किया.